Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Raghuvir Singh
Shastri, Shri Shiv Kumar
Shinkre, Shri
Shiv Charan Lal, Shri
Singh, Shri J. B.
Sivasankaran, Shri
Somasundaram, Shri S. D.
Subravelu, Shri
Tyagi, Shri O. P.
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Vidyarthi, Shri R. S.
Viswanathan, Shri G.
Xavier, Shri S.
Yadav, Shri Ram Sewak

MR. SPEAKER : The result of the division is Ayes 224; Noes 75*

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : The House will now take up the half-an-hour discussion.

18.10 hrs.

†FOURTH FIVE YEAR PLAN

श्री श्रीचंद गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मधु लिमये (मुंगेर) अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हम लोगों को खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश के जिन दो मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था,—उन को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया था या नहीं, उसके बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं—उनके साथ अदालत में दुर्व्यवहार किया गया है, उनको घसीटा गया है। इसलिए गृह मंत्री महोदय को इस बारे में सफाई देनी चाहिए।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, अगर वह ठीक है, तो यह बहुत निन्दनीय बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ऐसी बहुत सी घटनायें हो रही हैं। हमारे मंत्रियों को तो अदालत में घसीटा जा रहा है और हमारे विद्यार्थियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, यह हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य दें।

MR. SPEAKER: I have already admitted it; it is coming up tomorrow morning.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी वहां से आया हूं।

MR. SPEAKER: It may be so; you might have come from there; I am not denying it.

श्री रामसेवक यादव : मैं उनकी गिरफ्तारी के कानूनी पहलू में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि अदालत 5 बजे उठती है, इस लिए साढ़े पांच बजे मंत्रियों ने कहा कि अब अदालत का समय बीत गया है, अब कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, अब हम कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। तब वहां पर पुलिस और मैजिस्ट्रेट ने उनको घसिटवाया, उनके कुर्ते फट गये। वहां पर छाबड़ा, डी० एस० पी० और कपूर, मैजिस्ट्रेट थे।

MR. SPEAKER: That also, the Minister will take note of, in making his statement.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The Home Minister is there; let him make a statement. This is happening under your nose; it is Parliament's business to take note of it.

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) अध्यक्ष महोदय, इस समय यूनिवर्सिटी के तीन मील के इलाके में वर्चुअली कर्फ्यू लगा हुआ है। दफ़ा 144 के नाम पर सैकड़ों सिपाही और दर्जनों मैजिस्ट्रेट लोगों को रोकने में लगे हुए हैं। वहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन उनको न बाहर जाने की इजाजत है और न अन्दर जाने की। एक तरह से उन सबकी हाउस एरेस्ट की हुई है। सरकार वहां पर कानून का दुरुपयोग कर रही है। वहां पर एक प्रकार से कर्फ्यू लगा हुआ है। यह बड़े शर्म की बात है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल।

श्री श्रीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय, चौथी पंच-वर्षीय योजना की छुट्टी कर दी गई

---

*Shri Raghuvir Singh Shastri also noted for 'Noes'. Hence, the actual figure for 'Noes' is 76.

†Half-An-Hour Discussion.

है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना को पूर्ण हुए दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन इस संसद् में इस पंच-वर्षीय योजना की पूर्ति के लिए आज तक कभी विवाद नहीं मांगा गया है, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। यहां पर स्वेतलाना आदि के कई प्रश्न लाए गए लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दुर्लक्ष किया जा रहा है, जिस पर देश का विकास, देश के भविष्य की समृद्धि निर्भर है।

18.14 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं निवेदन करना चाहता हू कि पंच-वर्षीय योजना के ऊपर हमारे देश की भविष्य की समृद्धि निर्भर है। इन योजनाओं के द्वारा हम अपने राष्ट्र के साधनों का न्यूनतम समय में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए हम वर्तमान समय में त्याग और परिश्रम कर के अपने भविष्य की समृद्धि को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि इस योजना की छुट्टी कर दी गई है और उसके स्थान पर हमें एक एक वर्ष की योजना के नमूने दिये जा रहे हैं। वास्तव में जनसंघ ने तो यह मांग की थी कि पंचवर्षीय योजना की अवधि बढ़ा दी जाये, ताकि हम इस पर विचार कर सकें कि लम्बे काल के लिए अपने देश के साधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाये।

18.15 hrs.

[SHRI G.S. DHILLON *in the Chair*]

हमें कहा गया कि हमारे सामने दो कठिनाइयां आ गई थीं, जिनके कारण हम चौथी पंचवर्षीय योजना को सिरे नहीं चढ़ा सके : एक तो पाकिस्तान का आक्रमण और दूसरे, लगातार दो वर्ष का सूखा। यह कहा गया कि इन दो कारणों से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम इन योजनाओं के द्वारा इस बात की व्यवस्था नहीं करते हैं कि हमारे मार्ग में जो कठिनाइयां आयेंगी, हम उनको पार करेंगे, उनमें से रास्ता निकालेंगे। आखिर इससे पहले की तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाइयां हमारे सामने आई। लेकिन हम लक्ष्यों में कुछ फेर-बदल कर के, कुछ एडजस्टमेंट कर के, इन योजनाओं को सिरे चढ़ाते रहे।

जब से हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री ने यह महकमा सम्भाला है, तब से उन्होंने इस योजना की छुट्टी ही कर दी है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने देश के विकास को ध्यान में रखा है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इन योजनाओं के अन्तर्गत देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रबन्ध किया जाता है। नेहरू जी इसी कारण इन योजनाओं पर इतना बल देते थे और प्रयत्न से इन योजनाओं को सिरे चढ़ाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन योजनाओं की ओर दुर्लक्ष किया जा रहा है।

हम इन योजनाओं की पूर्ति में दूसरे देशों की नकल न करें, हम चीन और रूस आदि देशों के हथियार न अपनायें, लेकिन हम यह तो विचार कर सकते हैं कि हमें अपने देश की समृद्धि के लिए अपने देश के साधनों को जुटाना पड़ेगा। किसी भी देश की आदर्श योजना का लक्ष्य हमेशा यह होता है कि देशवासियों को पूर्ण रोज़गार मिले, देश को आत्म-निर्भर बनाया जाये, देशवासियों को न्यूतम जीवन-स्तर की गारण्टी दी जाये और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाये। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा योजना आयोग कुछ अपने ही विचार लेकर चलता है, वह देश की आवश्यकताओं और साधनों का विचार नहीं करता। और इसी कारण वह आंकड़ों के इन्द्रजाल से बाहर नहीं निकलना चाहता।

इसलिए आज समय आ गया है कि एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाये, जो इस बात की जांच-पड़ताल करे कि हमारी पहली तीन योजनाओं में क्या क्या कमियां रहीं, अपने देश के साधन जुटाने और बाहर से मिलने वाली सहायता में क्या कमी रही और हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में क्या कमी रही। यह सत्य है कि तीन योजनायें पूर्ण

[श्री श्री चन्द गोयल]

होनें के बाद भी देश में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हम आज भी अपने देश को अन्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर नहीं बना पाए और हमें करोड़ों रुपये का अन्न विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि हमने अपनी योजनाओं की प्रायर्टीज, वरीयतायें, गलत तय की थीं, हमने यह तय नहीं किया कि हम कृषि की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे और हम अपने देश में अपनी जनसंख्या को देखते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करेंगे। हमारे देश में सत्तर प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते हैं, तथा खेती पर निर्भर हैं। इसलिए हमें सबसे पहली वरीयता खेती के उत्पादन को बढ़ाने को देनी चाहिए थी।

आज पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं उनसे भी यह सिद्ध हो गया कि हमने अपने रक्षा-उद्योग की तरफ जिस प्रकार का ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया। और भी किसी प्रकार से हम देश को आत्म निर्भर नहीं बना पाये। जनसंघ ने तो अनेकों बार सुझाव दिए थे 1952 में जनसंघ ने कहा था कि योजनाओं की वरीयता को बदलना चाहिए। इनके अन्दर परिवर्तन किया जाय। इनके जो लक्ष्य हैं वह देश की स्थिति को देख कर निर्धारित करने चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि ग्रामों के अंदर रहने वाले जो किसान हैं यह भी मुश्किल से साल में आठ नौ महीने काम में लग पाते हैं, तीन चार महीने बिलकुल बेकार रहते हैं, उनके लिए भी कुछ काम निकाला जाय। लेकिन क्या हमने अपनी योजनाओं के अन्दर उन छोटे-छोटे उद्योगों और यंत्र चालित उद्योगों को बढ़ाने की कोशिश की है और खेती को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। ग्रामवासियों की समस्या हल करने के लिए हमें छोटे यंत्र चालित उद्योगों पर बल देना चाहिए था। हमारी योजना का लक्ष्य होना चाहिए था कि देश वासियों को, हर एक व्यक्ति को, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। उसके लिए हम खेती के ऊपर बल दें। उसके साथ-साथ जो यंत्र चालित छोटे उद्योग हैं उनके ऊपर भी बल दें। घरेलू उद्योगों के ऊपर बल दें और बिजली की पैदावार के लिए विशेष बल दें। यह जो देश की जरूरतें हैं उनकी ओर हमने आज तक दुलक्ष्य किया है और आज जैसा कि मैंने निवेदन किया, मानो हमने इस योजना की छुट्टी कर दी है, तीन साल की छुट्टी। नेहरू जी कहा करते थे कि आराम हराम है और लोगों को काम करना चाहिए, काम में लगना चाहिए। लेकिन आज जो प्रेरणा देनेवाली योजनाएं थीं, जिससे कि देश के सारे राज्य अपने-अपने साधन जुटा कर और एक लम्बे समय के लिए एक इस बात की प्रेरणा लेकर जुटा करते थे, उसमें अब एक काम्प्लेसेंशी का वातावरण देश के अन्दर फैलता जा रहा है। लोगों को लगता है कि सब ठीक है। हालांकि इस वर्ष की बात की अपेक्षा है कि बहुत बढ़िया फसल होने वाली है, उसका हम उपयोग कर सकते थे और उसी प्रकार सब राज्यों के लोगों को इस बात की प्रेरणा दे सकते थे कि वह इस योजना की पूर्ति के लिए जिस प्रकार साधन जुटाने की आवश्यकता है वह साधन जुटायें लेकिन इन योजनाओं को छुट्टी देकर हमने एक छुट्टी का वातावरण निर्माण कर दिया है जिससे लोगों को लगता है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस सदन के अंदर भी सदस्यों को जितना ध्यान देकर इसके ऊपर विवाद मांगना चाहिए था और हमारी सरकार की आंखें इस योजना की तरफ से ओझल हो गई हैं उस तरफ ध्यान दिलाना चाहिए था, वह भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं आज इस आधे घंटे के विवाद के द्वारा इस बात की आवश्यकता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम इन योजनाओं की छुट्टी न करें बल्कि उनको पूरी गंभीरता के साथ पूरा करें, जिम्मेदारी के साथ इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें और साधन जुटाने की कोशिश करें। देश की आवश्यकता को देखकर उसके लिए

लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के अनुसार वरीयता तय करें और लक्ष्य निर्धारित करें।

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, योजना, आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि अगले तीन साल के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी। योजना आयोग के इतिहास को अगर देखा जाय जब नेता जी सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन दिनों से योजना की भावना हिन्दुस्तान में आई। इसके बाद पिछले वर्षों में जिस दिन से योजना आयोग बैठाया गया है आप देखेंगे एक तरफ से योजना चल रही है, दूसरी तरफ पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है और यह सारा हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। यह बाकायदा तीन रपटें आपके सामनें हैं—एक महालनवीस कमेटी की रपट है, एक मोनोपली कमीशन की रपट है और एक हजारी कमीशन की रपट है। कुछ मुट्ठी भर व्यावसायिक परिवार देश की सारी आर्थिक नीति के ऊपर छा गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि प्लान्ड एकोनामी का क्या यह मतलब है कि एक तरफ योजना चल रही है और दूसरी तरफ पूंजीवाद बढ़ रहा है? मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या योजना का आधार जो हमारा चल रहा है कि खपत का आधुनिकीकरण करो, उत्पादन का आधुनिकीकरण बन्द कर दो क्या यह सही आधार योजना का है? खपत का आधुनिकीकरण करके, हिन्दुस्तान के नौकरशाह, पूंजीवादी लोग और मंत्री लोग यह तीन, षडयंत्र करके जनता को भूखा रखना चाहते हैं। इसलिए मैं साफ पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री और इनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष गाडगिल साहब कोई नये सिरे से सोच रहे हैं कि कैसे हिन्दुस्तान की योजना को बनाया जाय? क्या वह यह सोच रहे हैं कि खपत के आधुनिकीकरण को अगले 2 साल के लिए बंद किया जाय और पन्द्रह सौ से ऊपर जो खर्चा करते हैं, उनके ऊपर पाबन्दी लगायी जाय ताकि तीन चार हजार करोड़ की बचत हो सके जिसके द्वारा हम किसान के लिए पानी का इन्तजाम कर सकें। अभी 26 करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिसको पानी नहीं मिलता है और इन्द्र पर उसके लिए निर्भर करते हैं जिससे उत्पादन नहीं बढ़ता है और पी० एल० 480 तथा अन्य देशों की सहायता पर निर्भर होना पड़ता है कि यहां से जब गेहूं या चावल आयेगा तब हम अपने लोगों को खिला पायेंगे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कोई इस तरह की योजना है कि अगले पांच सालों में यह जो २६ करोड़ एकड़ भूमि बिना पानी के है उसको पानी दिया जाय? सरकार की कोई नीति हो जिसके चलते किसान को उत्पादन करने के लिए क्षमता मिले और जो फिजूलखर्ची है, शान-शौकत और वैभव है उसको खत्म किया जाय। क्या इस तरह की कोई उनकी भावना या चिन्ता है या नहीं?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चैयरमैन साहब, कहत के कारण हमारी योजना मुल्तवी कर दी गई। मैं समझता हूं कि इस मौके पर हमें सारे प्लान को दोबारा सोचने और बनाने की जरूरत है। मैं सिर्फ यह सवाल मैडम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि आज जबकि बाहर के देशों से हमें अनाज लेना पड़ता है और तौहीन हमारे देश की है, इस हालत में कोई प्लानिंग ऐन्युवल या चौथे पांच साला का जो प्लान बनेगा उसमें खास तौर से किसान को चीप क्रेडिट देने की बात सोची जायगी जिसमें लम्बे अरसे के लिए आसान किस्तों में वह लोन अदा करने की सहूलियत किसान को दी जायगी? 1 हजार करोड़ रुपया तो एल० आई० सी० के पास है और जो जनरल इंश्योरेंस का रुपया है इसके अलावा सोशल कंट्रोल करके जो हम लायेंगे उस रुपये को ज्यादा से ज्यादा इरीगेशन किसान को देने के लिए, उसको ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट देने के लिए पांच पांच, सात सात दस दस और पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपये उसे आसान किस्तों में थोड़े ब्याज पर देंगे?

[श्री रणधीर सिंह]

दूसरी बात, ट्रैक्टर के मुताल्लिक है। आज कल पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस हजार रुपये में एक ट्रैक्टर मिलता है। तीन चार हजार रुपये में ट्रैक्टर किसान को मिल जाय इसके लिए कोई इंतजाम करेंगे ? क्या कोई इस किस्म का रुपया योजना में रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कारखाने यहां खोले जायं बजाय इसके कि बाहर से मंगाए जायं ताकि किसान को मिनिमम प्राइस पर ट्रैक्टर दिए जाएं जिनसे वह ज्यादा से ज्यादा खेती करे ?

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे ही चीप फर्टिलाइजर के लिए कोई इंतजाम करेंगे ? देश में सस्ता फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा दिया जा सके इसके लिए कोई ध्यान दिया जायगा ? आजकल जो फर्टिलाइजर दिया जाता है वह किसान की रीच के बाहर है। तो कोई ऐसी सब्सिडी देकर या और किसी तरह से मास स्केल पर फर्टीलाइजर पैदा करने के लिए आप इंतजाम करेंगे ? यह आप अगर कर सकेंगे तो जो आज जो प्रोडक्शन है किसान का वह दुगुना और तिगुना हो जायगा। इस तरह का कोई प्लान प्राइम मिनिस्टर साहिबा बनाएंगी जिससे देश का मसला हल हो ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारी सारी योजनाएं और योजना बनाने का काम चौपट हो गया है। इन्होंने योजना कमीशन के उपाध्यक्ष के लिए हमारे मित्र का नाम तय किया और वह वहां जाते ही, उन्होंने सारी योजनाओं को ही खत्म कर दिया ....

एक माननीय सदस्य : कौन मित्र हैं ?

श्री मधु लिमये : अशोक मेहता जी के वहां पहुंचते ही सारी योजनाएं खत्म हो गईं। अध्यक्ष महोदय, अब प्रधान मंत्री जी ने चूंकि इसका बोझ ले लिया है अपने सिर के ऊपर तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर सोचा है, सोवियत रूस से योजना बनाने की कल्पना तो इन्होंने ले ली लेकिन यह भूल गए कि सोवियत रूस में अर्थ-व्यवस्था में, समाज-व्यवस्था में, बुनियादी परिवर्तन लाने के पश्चात् योजना की इमारत खड़ी की गई। हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था है, जो नौकरशाही चौखट्टा है, उसको कायम रख कर योजना बनाने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि करीब-करीब 17 साल हो गये, आज हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि चौथी योजना को अन्तिम रूप भी हम नहीं दे पाये हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब अगली योजना अपने देश में आयेगी तो वे इस बात का खयाल रखेंगी कि कोई भी योजना नहीं बन सकती जब तक कि कोई दाम नीति न हो। आज उत्तर प्रदेश में गेहूं के दाम और गन्ने के दाम दोनों में इतना फर्क हो गया है कि जो खेत गन्ने के लिये पहले इस्तेमाल में लाये जाते थे, उनमें अब लोग गेहूं बोने लगे हैं। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती में एक एकड़ म 6 हजार रुपये की आमदनी होती है, जबकि बाजरा, नये ढंग का बाजरा लगायें तो 11-12 सौ रुपये मिलते हैं—तो यह दाम नीति नहीं है। इनकी कोई उद्योग नीति नहीं है। जैसा कि अभी रवी राय ने कहा कि उद्योगों में सम्पत्ति और आर्थिक सत्ता का एकीकरण हो रहा है, उसके बारे में इनके पास कोई नीति नहीं है। मजदूर नीति भी नहीं है, बहुत सारे मजदूरों के झगड़े जो उत्पन्न हो जाते हैं —उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि अनिवार्य रूप में युनियनों को मान्यता देने के लिए इन्होंने कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया और न यह तय किया कि प्रतिनिधिक यूनियन कौन है। यह मतदान के द्वारा, बैलेट के द्वारा निश्चित किया जायगा। तो इनके पास कोई श्रम नीति नहीं है।

प्रधान मंत्री जी को यह भी याद होगा कि पिछले बजट सत्र के प्रारम्भ में वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि इस साल मुद्रास्फिति को रोका जायगा, डेफिसिट फाइनैन्सिंग नहीं होगा और अब वित्त मंत्री

जी ने स्वीकारा है कि सरकार का जो खर्च है और सरकार की जो आमदनी है, उसमें इतना बड़ा अन्तर आनेवाला है कि उसका लाजमी नतीजा होगा कि मुद्रास्फिति होगी, डेफिसिट फाइनेन्सिग होगा और साथ ही साथ दाम बढ़ेंगे । काला बाजार बढ़ेगा और जखीरेबाजों को मौका मिलेगा । तो चौथी योजना बनाते समये ये जितने पहलू हैं—पूंजीकरण का सवाल, दाम नीति का सवाल, श्रम नीति का सवाल, उद्योग नीति का सवाल और यह मुद्रास्फिति का सवाल—मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री जी इन सब पर विचार करेंगी ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह पंचवर्षीय योजना जो एक तरह से ठप्प होती नजर आ रही है और जो यह सालाना योजना चलाई जा रही है, इसके पीछे एक वजह है—यह चीज इन्होंने खुद पैदा की है, यानी अब तक इन योजनाओं में जो अर्थ-व्यवस्था निकली है, उसी की वजह से यह परिस्थिति आ गई है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अभी भी लागू नहीं हो रही है । वह परिस्थिति क्या है ? वह पूंजीवादी परिस्थिति है । तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय अर्थ-व्यवस्था का क्या हुआ है—भारतीय पूंजीवाद का विकास हुआ है । पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारतीय पूंजीवाद का विकास हुआ और यह विकास पूंजीवादी चाहते थे, इसलिये पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना चाहते थे । लेकिन अब वह देख रहा है, इस योजना से उसको खतरा है, चूंकि समाज चाह रहा है कि पूंजीवाद का खात्मा हो और समाजीकरण हो, उत्पादन के साधन पर समाज का कब्जा हो— यह समाज का तकाजा है, इसलिये अब भारतीय पूंजीवाद चाहता है कि इस पर रोक लगे और उसकी वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत नहीं हो रही है । कहते हैं कि अब इनके पास साधन नहीं हैं ···

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री शिव चन्द्र झा : वह पूंजीवाद अब चौथी योजना को रोक रहा है और कहा जात है कि इसके लिये मुल्क में साधन नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क में साधनों की कमी नहीं है, आप आमदनी पर रोक लगा दीजिये, एक और दस की रेशो हो तो एक हजार करोड़ रुपया आप के पास आ जायगा । प्रीवी पर्स रोक दिया जायगा तो 500 करोड़ रुपये सालाना आपके पास आयेंगे, टैक्स इवेजन को मुस्तैदी से रोका जायगा तो दो-तीन सौ करोड़ रुपया आ जायगा । समाज में साधन हैं, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है, लेकिन इस सरकार में इतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है और नीयत भी नहीं है, जिसकी वजह से साधन घट रहे हैं बल्कि उनका उपयोग नहीं हो रहा है ।

आज विदेशों से भी हमको साधन की जरूरत नहीं है । कृषि में और उद्योगों में हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा । कृषि की पैदावार हम तभी बढ़ा सकते हैं जबकि हम क्वालिटेटिव चेन्ज लायें, लैंड रिफार्म्ज मुल्क में ज्यादा किये जायें—लेकिन यह तभी होगा जब हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये कदम उठायेंगे । अब तक जितने लैंड रिफार्म्स हुए हैं, जितने सुधार हुए हैं—वे उपयोगी नहीं हैं, फ्रैगमेन्टेशन आफ होल्डिज को तोड़ कर इकट्ठा करना होगा, तभी हमारी कृषि की पैदावार बढ़ेगी । उसी तरह से उद्योगों में भी हमको मजदूरों का पार्टीसिपेशन उद्योगों में लाना होगा, वर्कर्स का पार्टीसिपेशन मैनेजमेन्ट में होगा, तभी उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा । ऐसा करने से ही कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा और फिर इन साधनों को इकट्ठा करने से हमारे पास पर्याप्त साधन आ जायंगे जिससे हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना को अपनी पूरी ताकत से लागू कर सकते हैं—लेकिन इसके लिये हमें अपने सामने आदर्श रखना होगा—सम्पत्ति और समानता का । हमें पूंजीवादी विकास को रोकना होगा, उत्पादन के साधनों को समाज में ज्यादा करना होगा, मुनाफाखोरी को खत्म करना होगा यानी पूंजीवाद

[श्री शिव चन्द्र झा]

को खत्म करना होगा, तभी हमारी योजनायें आगे बढ़ सकती हैं।

सभापति महोदय : मैं आपको बतलाऊं कि आधे घन्टे के डिस्कशन में आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपने तो लम्बा-चौड़ा भाषण कर दिया—यह बात गलत है। श्री भगत।

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): Sir, today, in the morning, I had written to the Secretary, Lok Sabha, during the Question Hour, that I may be allowed to put a question on this.

MR. CHAIRMAN: Seven names were received and they were balloted. Only four names were selected.

SHRI S. M. BANERJEE : In that case, I will be forced to say, "Lok Sabha, thy name is lottery!" Even the names are balloted for putting questions.

MR. CHAIRMAN: You have the rules. Under the rules, they balloted the names. The rules are yours.

SHRI S. KUNDU (Balasore); You may kindly give us a minute each.

MR. CHAIRMAN: If I give a minute each, then you mean there should be no ballot.

SHRI E. K. NAYANAR: Just a minute.

MR. CHAIRMAN: All right; you may ask a question in a minute.

SHRI E. K. NAYANAR: Sir, there have been three Plans and after three Plans, not only the monopoly has developed but also the regional disparity has developed. Some of my friends have said that monopoly has developed, unemployment has developed, and the regional disparity has also developed. During the last three Plans, in the Central sector, Rs. 2,852 crores were invested and, during the same period, in Kerala, only Rs. 27·19 crores were invested. According to the population, Kerala has the right to get Rs. 101·07 crores. This is the regional disparity. Not only that. Take the *per capita* figures. During the last 15 years, the *per capita*, on all-India level, was 26·5 per cent but in Kerala the *per capita* was only 16·8 per cent. In 1963-64 the average income was Rs. 332·9 whereas the income of a Kerala man was only Rs. 219·94. The one point that I want to impress upon is the regional disparity and our Prime Minister must take into account the needs of Kerala, the industrial backwardness, the unemployment and all that. Even the setting up of the precision tools factory has been postponed and so is the case of the shipping industry. This regional disparity must be taken into account by the Prime Minister before finalising the Fourth Plan.

SHRI S. KUNDU : Sometime back, the Prime Minister had laid a statement on the Table of the House setting out the reasons as to why the Fourth Plan was shelved for the time being and in that, the Prime Minister has stated about Pakistan aggression, drought and other things. But I would like to say that similar conditions were also there before 1965. In 1962, there was the Chinese aggression, and nobody can also say that in future such things would not come. Therefore, can this be the reason to scrap off the Plan, more so when the Draft Plan was prepared. If a Draft Plan was prepared, why not an integrated Plan was developed ? It is precisely because of this. Government is playing into the hands of bureaucrats and big capitalists who manoeuvre to see that there is no Plan for some time in this country. It has been said that there are meagre resources. First of all, when Mr. Ashoka Mehta came here as the Deputy Chairman of the Planning Commission, he tried to bring out a gigantic Plan; he was somewhere on a different plane, where he was thinking of putting up a Rs. 21,000 crore Plan. Now, a completely lopsided view of this Government is seen—no Plan or a Plan Holiday.

MR. CHAIRMAN : He may ask his question.

SHRI S. KUNDU : I would like to ask only one question.

One of the criteria of planning is to check the imbalances in the country. The object was to develop, through this planning, the less developed States and to divert the resources to those States. Take, for instance, Orissa. I come from Orissa where the Prime Minister was going when her father was going—she decided to go there but she cancelled her trip; then she

fixed it during the cyclone time. Last year, they gave to Orissa only Rs. 21 crores and now for 1968-69 they are trying to reduce it still further. The question is this. The object of planning is to check the imbalance, but what they are doing goes against it.

MR. CHAIRMAN : He may finish now.

SHRI S. KUNDU : My final question is this. I would like to ask the Prime Minister who is in charge of planning and who is the Chairman of the Planning Commission, what concrete steps they are going to take to stop this imbalance in planning, to stop the growing concentration of wealth in some of the developed States. And to set right planning as a whole in the entire country.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : I will just take half a minute..... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : I am not going to follow your advice any more. I have already allowed two members whose names were not balloted. Members whose names were not included in the list are getting up. I am sorry....

SHRI S. S. KOTHARI : I have given my name. I will take just half a minute. I would submit to the Prime Minister that there is an unexploited mine of resources in the public sector undertakings. Would she direct her attention to improve their working ? Would she appoint some high power technicians to look into the working of some of the major projects ? I assure her that if she does that, if the working of the public-sector undertakings improves, then she will get enough resources for any Plan.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के स्थगन से क्या राष्ट्र निष्क्रिय होकर बैठा रहेगा और राष्ट्र के लोगों से वह चुनाव के घोषणापत्र के द्वारा जो हम ने वायदा किया है उसका क्या होगा ?

विभिन्न योजनाओं के स्थगित हो जाने तथा उन से सम्बन्धित संस्थानों के बन्द हो जाने पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी और नागार्जुन सागर बांध के दूसरे चरण में सरकार की कितना पैसा देने की योजना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि योजना के प्रति लोगों का आदर भाव बढ़ता जा रहा है । उन क्षेत्रों में भी और उन लोगों में भी जो कि अभी तक योजना के प्रति इतने उत्साहित नहीं थे वह भी आज उस के प्रति उत्साहित हो रहे हैं । अभी जब उधर से हमारे एक भाई योजना के प्रति ज़ोर शोर से अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे थे तो यह मेरे पास बैठे हुए गुजराल साहब जो कि उर्दू के शायर हैं उन्होंने कहा कि यह तो भाई बड़ी अच्छी बात है और वह शेर जो उन्होंने मुझे सुनाया वह मैं सदन में सुना देना चाहता हूं :

"मैं बना काफिर तो वह काफिर
मुसलमां हो गये"

यह बड़ी खुशी की बात है और मैं इस का आदर करता हूं । वैसे मैं यह बतला दूं कि यह हमारे स्वतन्त्र पार्टी वाले और यह फेडरेशन आफ चैम्बर आफ कामर्स वाले लोग 15—20 साल से कहा करते थे कि सरकार बड़ी-बड़ी योजनाएं बना कर देश को बर्बाद कर रही है और यह कि हमारा प्लान बड़ा नहीं होना चाहिए और इनवैस्टमेंट छोटा होना चाहिए अब आज उन्हीं लोगों की तरफ़ से मांग हो रही है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए और यह आज कम क्यों हो रहा है ?

यह अच्छी बात है । साथ साथ हमारे और दोस्तों ने जो और सवाल उठाये हैं उन में बहुत सारे सवाल हैं जिन में कि दो राय नहीं हैं । मैं मानता हूं कि आज बड़े मौलिक सवाल उठाये गये हैं लेकिन उन बातों का इस आधे घंटे की बहस के दरमियान पूरे तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता है और इस वक्त अगर मैं उनमें तफसील में न जाऊं तो इस के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे ।

[श्री ब० रा० भगत]

बहुत सी बातें कही गईं, जैसे क्षेत्रीय असमानता है वृद्धि में, विकास में और यह रीजनल डिस्पैरैटीज की बात है। अब आम तौर से यह हमारा अनुभव रहा है और यह बात सही है कि हम चाहते हैं कि तेजी से तरक्की हो सारे देश की। उस के दरमियान में हर प्रान्त के लोग हमें कहा करते हैं कि हमारा प्रान्त पीछे रह गया और अभी इस बारे में दो प्रान्तों के भाइयों ने कहा तो जल्दी से मेरे पास जो आंकड़े मौजूद थे मैं ने उन में देखा। अभी तक उन दो प्रान्तों में से, जैसे केरल का सवाल है जहां एक व्यक्ति पर पूरा उन का इनवैस्टमेंट हुआ है तो आप देखेंगे कि एक आदमी पर वहां 180 है और उन को मदद बाहर से कितनी मिलती है? 109। दूसरे ऐसे प्रान्त बहुत हैं जहां 100 के नीचे है। उड़ीसा का कहा गया। उड़ीसा तो बहुत कुछ आगे भी है और यह खुशी की बात है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दरमियान में उड़ीसा ने विकास की गति में वृद्धि की और यह अच्छी बात है। इस का नतीजा यह हुआ कि वह कई प्रदेशों को छोड़ कर आगे बढ़ गया। वहां एक व्यक्ति पर जो विकास पर खर्चा किया गया वह 217 एक व्यक्ति पर था।

एक माननीय सदस्य : राज्यवार ब्योरा दे दिया जाय।

श्री ब० रा० भगत : अभी इस समय नहीं वह किसी दूसरे समय दे दूंगा। वह तो जो बात उन्होंने उठाई थी उस के जवाब में मैं ने कहा।

इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश को देखियेगा। वहां बहुत कम है। एक आदमी पर 126 आता है। एक व्यक्ति पर विकास के लिए इतना खर्चा हुआ।

श्री मधु लिमये : बिहार में क्या है?

श्री ब० रा० भगत : बिहार में भी कम है। वह तो मैं उदाहरण के लिए यह कह रहा था बाकी असल बात तो यह है कि जो क्षेत्रीय विकास में असमानता है, रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उन को दूर होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उस के लिए आप की क्या योजना है?

श्री ब० रा० भगत : हर बात में हस्तक्षेप करने से जवाब नहीं दिया जा सकता। मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूं उसे पहले शांति से सुन लीजिये। क्षेत्रीय विकास में जो असमानता है उस को थोड़ा दूर करना चाहते हैं। यह जो असमानता सैकड़ों वर्षों में हुई है वह 2–4 वर्ष में दूर नहीं हो सकती। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस में दो राय नहीं हैं। हम एक नीति बना कर योजनाबद्ध तरीके से इसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं कि क्षेत्रीय विकास में असमानता न हो और वह जितनी जल्दी हो सके मिट जाय। उसी तरह से हमारे श्री रणधीर सिंह ने किसानों के लिए कहा कि सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये, ट्रैक्टरों का होना चाहिये, खाद का होना चाहिये। दूसरे भाइयों ने भी कहा है कि इनका प्रबन्ध होना चाहिये। इनका प्रबन्ध हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता इनका प्रयोग बढ़ाया जा रहा है।

मधु लिमये जी ने बुनियादी बातों की ओर ध्यान दिलाया है। योजना का अर्थ यह नहीं है कि एक आध स्कीम को ही हम चला लें। योजना जब बनती है तो उस के पीछे एक आदर्श होता है। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसको हम उस में स्वीकार करते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमने परस्पैक्टिव प्लानिंग के जरिये इसको करने की कोशिश की है। हमने कहा है कि पन्द्रह साल या पच्चीस साल में हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। उसमें बुनियादी परिवर्तनों की बात थी, उस में समाजवादी व्यवस्था की बात थी। अर्थ में या और दूसरी बातों में जो असमानता आ गई है या कुछ पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ती जा रही है उसको रोकने की

बात हमने कही । इस सब के बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं । बुनियादी बातों के बिना यह हो नहीं सकता है । यह कहना कि सोवियत संघ से हमने योजना उधार ली ठीक नहीं होगा । सोवियत संघ ने योजना चलाने की परिपाटी में बहुत अच्छा काम किया है, वह हमारे देश से बहुत आगे है और बहुत उसने काम किया है, इसको हमें मानना होगा । हम पर उसका असर भी पड़ा । हमने उनसे सीखा भी है । लेकिन हमारी व्यवस्था अलग है उनकी अलग है । मौलिक परिवर्तनों के साथ हमने उसको दिया, डेमोक्रेसी के जरिये किया, लोगों की रजामन्दी से किया । लेकिन आज सब से बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि हम योजना के लिये किस तरह से पूंजी एकत्र करें । आज सब से बड़ा यह चैलेंज हमारे सामने है । नेशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल में भी यह बात उठी थी । इस साल नौ करोड़ चालीस लाख या नौ करोड़ पचास लाख टन अनाज पैदा होने जा रहा है पिछले साल योजना के दर्म्यान में दो हजार करोड़ रुपया गांवों में गया है । गांवों के विकास में वह लगा है । सवाल पैदा होता है कि उसको वापिस ले कर कैसे लगाया जाए । जब वापिस लेने का सवाल आता है तो आवाज उठती है कि किसानों पर ज्यादा जोर न पड़े, भार न पड़े । फिर दामों की बात भी की जाती है । यह भी कहा जाता है कि और जो बातें हैं उनको देख कर किया जाए । फिर भी यह देखना होगा कि गांवों में जो रुपया जाता है वह किन को जाता है । दस बारह परसेंट आदमी हैं जिन के पास सारी सुविधायें हैं, सिंचाई की हैं; बीज की हैं, खाद की हैं । और यह रुपया भी अधिकांश में उन पर ही खर्च हो जाता है, वही इस रुपये से फायदा उठाते हैं । किस तरह से अब उस रुपये को वापिस लिया जाए और पूंजी के रूप में उसको दुबारा लगाया जाए, यह भी देखना होता है ।

फिर यहां रोजगार की बात कही गई है । यह कहा गया है कि लोगों को पूरा रोजगार मिलना चाहिये । यह भी ठीक बात है । फिर जीवन स्तर को उठाने की बात भी कही गई है । यह कहा गया है कि जो हमारी न्यूनतम जरूरतें हैं, कपड़े की है, दवा दारू की है, शिक्षा की है, मकान की है, भोजन की है वह तो पूरी होनी चाहिये । ये बुनियादी आवश्यकतायें लोगों की पूरी तो हों । ये जरूरतें भी लोगों की हम पूरी नहीं कर पाये हैं । एवरेज जो आदमी है, जो गरीब आदमी है वह एक रुपया रोज भी तो नहीं कमा पाता है, आन एन एवरेज भारत में एक आदमी की आमदनी एक रुपया रोज भी तो नहीं होती है । इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । इन सब चीजों को योजना में बांध कर जितनी हम को बड़ी योजना चाहिये, जितनी हम को पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिये, वह सब हम करने का प्रयत्न करते हैं ।

तफ्सील की बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूं । सवाल यह है कि जो सारी शक्ति है, मनुष्य की शक्ति है और आर्गेनाइजेशन की जो है सब की शक्ति लगा कर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं । मौलिक चेंजिज करके इंस्टीट्यूशनल चेंजिज करके हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ।

जो एक मुख्य बात उठाई गई है, उस पर मैं आता हूं । यह आक्षेप किया गया है कि हमने योजना की छुट्टी कर दी है, योजना को समाप्त कर दिया है । योजना की छुट्टी नहीं हुई है । इस तरह की बात कहना बिल्कुल भ्रम फैलाना है । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तब हम को योजना को स्थगित करना पड़ गया । एक माननीय सदस्य ने कहा कि चीन ने भी तो हमला किया था और तब आपने योजना को स्थगित नहीं किया था । आपको याद होगा कि इस चीज को सदन के सामने रखा गया था और बताया गया था कि पाकिस्तान के आक्रमण के बाद एक ऐसी

[श्री ब० रा० भगत]

स्थिति पैदा हुई कि बाहर की जितनी सहायता मिलती थी, दूसरे देशों से जितनी सहायता मिलती थी वह सहायता लगभग बन्द कर दी गई। तब देश में यह खयाल हुआ कि हम अपनी योजना को इस तरह से बनायें, उस में इस तरह से परिवर्तन करें कि हम स्वावलम्बी बन सकें, अपने ही बल पर योजना को चला सकें। उस चीज को सदन में लाया गया था और सदन ने कहा था कि हम योजना को उस तरह से परिवर्तित करें। यह एक मौलिक बात हो गई, एक बड़ी बात हो गई। सारी योजना के बारे में सदन से सैंक्शन ले कर ऐसा किया गया, सदन के आदेश पर ऐसा किया गया।

यह भी सवाल उठाया गया है कि हम स्वावलम्बी कैसे बनें, बाहर से सहायता न भी मिले तो भी अपने पैरों पर कैसे खड़े रह सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही बल बूते पर जहां तक हो योजना को चलायें। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि विकास तेज गति से नहीं हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारा ही यह अनुभव नहीं है दूसरे देशों का भी यह अनुभव है कि विकास की गति उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ती नहीं गई है, एसेंडिंग आर्डर में हो रही हो, यह बात नहीं है। कभी नीची रही है और कभी ऊपर उठी है। हमेशा ही एसेंडिंग आर्डर में वह नहीं रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है और न होगा। मनुष्य की जिन्दगी में भी उतार चढ़ाव चलता है। उसकी जिन्दगी में भी इस तरह की चीज होती है। यह बात जरूर है कि हम अपनी योजना में ऐसी स्थिति पैदा करें, ऐसी नीतियां बनाएं, इस तरह के काम करें कि इन उतार चढ़ावों का असर और जो क्राइसिस पैदा होते हैं, उनका असर कम से कम पड़े।

आप जानते ही हैं कि दो साल तक सूखा पड़ा है, अकाल की स्थिति रही है। कितना बड़ा सूखा यह था इसको आप जानते ही हैं। आपको याद होगा कि योजना से पहले हमारे देश में आर्थिक वृद्धि एक परसेंट से भी कम होती थी। हम ने योजना बनाई तो हम ने कहा कि हम पांच प्रतिशत वृद्धि करेंगे। वह हम नहीं कर पाए। तीसरी योजना में हम साढ़े तीन परसेंट प्रतिवर्ष का विकास कर पाए हैं। वह कम है। लेकिन याद रखिये कि योजना में पहले एक प्रतिशत विकास भी नहीं होता था। पिछले दो सालों में साढ़े चार प्रतिशत नेशनल प्रोडक्टिविटी में गिरावट आई है। इतने मार्जिन पर हम थे। हमारे देश की आर्थिक स्थिति को जो यह झटका लगा यह मामूली नहीं था। दो साल सूखा पड़ा रहा। यह झटका मामूली नहीं था। लेकिन फिर भी हमने योजना को छोड़ा नहीं। इस झटके का असर निर्यात पर पड़ा, पूंजी पर पड़ा, रिसोर्सिस पर पड़ा।

यह कहना कि केन्द्रीय सरकार का बजट घाटे में चलता है इसको मैं मानता हूं। लेकिन दूसरी सरकारें भी हैं जो दूसरे आदमियों के हाथों में हैं। उन सरकारों के बजट भी आज पूरे नहीं हो पा रहे प्लान के। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह एक ऐसी दिक्कत है जिस को पार करके हमें आगे बढ़ना ही होगा। पंचवर्षीय योजना के बजाय हमने एनुअल प्लान बनाने की कोशिश की है। चौथी योजना का जो प्रथम वर्ष था उसके लिए हमने एनुअल प्लान बनाया। पंचवर्षीय योजना में जो प्रायोरिटीज थी, उसका जो साइज था, उसी हिसाब से हमने उसके लिए 2,200 करोड़ रुपया निर्धारित किया। 21,000 करोड़ रुपया जो पंचवर्षीय योजना के लिए रखा गया था उसी हिसाब से एनुअल प्लान के लिए हमने रुपया निर्धारित किया। 2,200 करोड़ रुपया भी जो हमने रखा वह बड़ी मुश्किल से रखा। लेकिन हम ज्यादा गिरना नहीं चाहते थे। जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय आय में गिरावट आ गई है उसको देखते हुए 2,200 करोड़ की योजना रखना भी मुश्किल था। लेकिन खेती के सवाल को तथा दूसरे जो खेती के साधन हैं या दूसरी

चीजें हैं उन को सामने रखते हुए हमने यह राशि निर्धारित की । चूंकि आज खेती की हालत अच्छी है इस वास्ते 14 प्रतिशत की वृद्धि हमारी राष्ट्रीय आय में होने जा रही है । आप फर्क देखिये अगर हमारी खेती की उपज 120 मिलियन टन हो जाए जो हमें आशा है कि आज नहीं तो कल हो जायगी तो हमारी राष्ट्रीय विकास की गति बहुत तेज हो जायगी ।

19 hrs.

इस साल का जो प्लान बना उसमें हमने उन बातों को जो हमें नीचे खींच रही हैं विकास में, उनको रोका और जो हम को आगे ले जायेंगी उनको लिया । खेती की हालत को हमने सुधारने पर जोर दिया । जो ट्रांजिशन की हालत है उसको हम कंसालिडेट कर रहे हैं ताकि 1969 के बाद जो प्लान बनेगा जो हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, हमारी राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़े, देश की मजबूती बढ़े, जिन पर आपने भी जोर दिया है । उनको हम अच्छी तरह सम्भाल सकें, उस सब का खयाल रख करके बनेगा । स्ट्रैटेजी तो हमारी यह है कि हम योजनाबद्ध विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे टेक्टिक्स बदलते रहते हैं । आज की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हम ने कानसालिडेशन के टैक्टिक्स अपना लिये हैं । अगर हम अपने टैक्टिक्स में परिवर्तन न करते और अपने तरीकों को न बदलते, तो हमें आगे और भी नुकसान होता । हमें आगे और नुकसान न हो और हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जायें, इसी लिए हम ने यह तरीका अख्त्यार किया है । यह कहना ठीक नहीं है कि प्लान होलिडे कर दी गई है या योजना की छुट्टी कर दी गई है । योजना में हमारा विश्वास है । हम मानते हैं कि इस देश में हम अपने लोगों के लिए सुख और समृद्धि तभी उपलब्ध कर सकते हैं, उन की हालत को भी तभी सुधार सकते हैं, अगर हम योजनाबद्ध विकास के मार्ग पर चलें । कई प्रकार की दिक्कतों के बावजूद योजना और योजनाबद्ध विकास में हमारा विश्वास है और हम और ज्यादा मजबूती के साथ उस मार्ग पर बढ़ते जायेंगे ।

19·03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 14, 1967/Agrahayana 23, 1889 (Saka).

97LSS(CP)/67—1010—9-3-68—GIPF. Δ